Intent issued for setting up new sugar units and for expansion of capacity:

Year	New Units	Substantial Expansion	Total
1994	66	29	95
1995	2	—	2
1996 (Upto Feb, 96)	—	4	4
Total	68	33	101

(b) to (e) The target for creation of capacity in the sugar sector during the Eighth plan period was 25.15 lakh tonnes of sugar. Plan targets for creation of capacity in any sector are indicative in nature and they by themselves do not suggest any capacity constraint in the sector. Receipt and processing of applications for Industrial Licences is an ongoing process. The Letters of Intent in any sector including the sugar sector is initially valid for 3 years which is extendable on merits of individual cases, during which during which time the letter of intent is required to be converted into Industrial Licence on fulfilment of conditions of Letter of Intent. The licence holder is required to commence commercial production within 2 years of obtaining the Industrial Licence.

उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग — 1992 की परीक्षा के परिणाम में अनियमितताएं

758. **मौलाना औबैदुल्ला खान आज़मी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा घोषित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा, 1992 के परिणामों के अनुसार 85% परीक्षार्थी केवल एक वैकल्पिक विषय अर्थात् संस्कृत से सफल हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या एक ही वैकल्पिक विषय के परीक्षार्थियों का सफल होना परीक्षाफल की संदिग्धता को दर्शाता है;

(ग) क्या इसमें बरती गई अनियमितताओं के कारण आयोग के तीन सदस्यों ने परीक्षाफल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो अनियमिताओं को समाप्त करने और परीक्षाफल को निष्पक्ष बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) और (ख) जी नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इस परीक्षा के लिखित इम्तहान के हाल ही में घोषित किए गए परिणामों में उम्मीदवारों की सफलता किसी एक वैकल्पिक विषय में प्राप्त अंकों पर आधारित नहीं थी।

(ग) जी नहीं। परिणाम की घोषणा आयोग के सभी सदस्यों के अनुमोदन से की गई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Privatisation of Irrigation Projects

759. SHRI PRAMOD MAHAJAN :
SHRI VIREN J. SHAH :
SHRI SANJAY DALMIA :
SHRI ISH DUTT YADAV :
SHRI K.M. KHAN :

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether the committee set up by Government to examine the feasibility, extent and modalities of privatisation in the light of inadequate funding and delays in completion of on-going irrigation projects, has submitted its report;

(b) if so, the details of the recommendations made by the Committee in respect of each project; and

(c) the present position of each of the on-going irrigation projects in Maharashtra and Gujarat which have been delayed on account of resource crunch and also the details of the projects which are proposed to be handed over to the private sector?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATE RESOURCES (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU) : (a) Yes, Sir.

(b) The Committee has not made any recommendations in respect of each Project. However, it has concluded that